

दि कर्मिक पोस्ट

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 12, अंक : 42

(प्रति बुधवार),

इन्दौर, 21 अक्टूबर 2026 से 27 अक्टूबर 2026

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

साफ-सुथरे शहरों का सपना कैसे होगा पूरा? नगर निकायों को अधिकार और संसाधन देना जरूरी

नई दिल्ली। भारत के किसी भी शहर की सफाई का फैसला हर सुबह नए सिरे से होता है। सफाई कर्मचारी अपनी तय जगहों पर काम करते हैं, कचरा उठाने वाले वाहन चालक अपने निर्धारित रास्तों पर चलते हैं और पर्यवेक्षण अधिकारी इस पूरे काम की निगरानी करते हैं। शहर की स्वच्छता इन्हीं लोगों की रोज की मेहनत पर निर्भर करती है। इसी काम को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री के निर्देश पर 29 सितंबर को 'प्रगति-50' की शुरुआत की गई।

इसके तहत 24 राज्यों के 50 शहरों में सफाई के काम को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल के तहत शहरों को यह साबित करना होगा कि वे लगातार बेहतर सफाई बनाए रखने में सक्षम हैं। इसके लिए सफाई से जुड़े प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के आधार पर काम का आकलन किया जाएगा। डिजिटल माध्यम से समीक्षा होगी और हर दो महीने में केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में बैठक भी की जाएगी। यह पहल

स्वागत योग्य है। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान के तहत पिछले एक दशक में बने ढांचे और चलाए गए अभियानों को रोजमर्रा की आदत में बदलना है। हालांकि, शहरों में सफाई की व्यवस्था तभी लंबे समय तक कायम रह सकती है, जब उनके पास अपनी पर्याप्त क्षमता और मजबूत संस्थागत व्यवस्था हो। महात्मा गांधी की जयंती पर 2014 में जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी तब देश के शहरों में केवल 16 फीसदी कचरे का प्रसंस्करण हो पाता था। इस साल मई में हुई राष्ट्रीय समीक्षा तक यह आंकड़ा बढ़कर 81 फीसदी हो गया। घर-घर से कचरा इकट्ठा करने की सुविधा 97 फीसदी वार्ड तक पहुंच गई और पुराने कचरे के ढेर वाले स्थलों से 65 फीसदी कचरा हटाया जा चुका है।

इस प्रगति का बड़ा हिस्सा उन कामों से आया जिन्हें मंजूरी देकर पूरा किया जा सकता था और जिनकी गिनती की जा सकती थी। शौचालयों का निर्माण इसका एक उदाहरण है। इसके साथ ही स्वच्छता अभियान ने लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाई और इसे नागरिक जिम्मेदारी तथा गर्व से जोड़ा। 'स्वच्छ सर्वेक्षण' ने भी शहरों के बीच बेहतर प्रदर्शन करने की होड़ पैदा की। इससे शहरों ने सफाई को गंभीरता से लेना शुरू किया।

अप्रैल से लागू हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 बताते हैं कि किसी शहर को साफ रखने के लिए कितने स्तरों पर तालमेल जरूरी है। इन नियमों के अनुसार, घरों को कचरे की चार श्रेणियों में छांटनी होगी। बड़े कचरा उत्पादकों को भी जहां संभव हो, अपने गीले कचरे का प्रसंस्करण खुद करना होगा। इसके बाद नगर निकायों की जिम्मेदारी है कि वे कचरा इकट्ठा करें और उसे उचित स्थान तक पहुंचाएं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाना है, जिला अधिकारियों को लैंडफिल स्थलों की निगरानी करनी है, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राष्ट्रीय पोर्टल का संचालन करना है। नियमों को लागू करने के लिए प्रत्येक राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई जानी है।

भारत में कचरा प्रबंधन से जुड़ी अलग-अलग एजेंसियों के बीच लगातार तालमेल बनाए रखना पहले भी मुश्किल रहा है। एक और समस्या यह है कि नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से कचरा पैदा करने वालों पर डाली गई है। लेकिन यदि किसी शहर के पास पर्याप्त वाहन, कर्मचारी या कचरे के प्रसंस्करण के लिए जरूरी संयंत्र नहीं हैं, तो अलग-अलग तरह के कचरे को अलग बनाए रखना मुश्किल हो जाता है।

इस्तेमाल किए जा चुके पानी के प्रबंधन में तो इससे भी अधिक एजेंसियां शामिल हैं। बड़े शहरों में सीवरेज व्यवस्था का संचालन अमृत योजना के तहत होता है जबकि एक लाख से कम आबादी वाले कस्बों में यह जिम्मेदारी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आती है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने 18 राज्यों के 393 शहरी स्थानीय निकायों का लेखा-परीक्षण किया। इसमें पाया गया कि 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर निकायों को सौंपे गए 18 कार्यों में से केवल चार पर ही उनका पूरा नियंत्रण था। औसतन पांच कार्य

ऐसी अलग-अलग एजेंसियों के पास थे जो सीधे नगर निकायों के अधीन नहीं आतीं। इसमें यह भी बात सामने आई कि नगर निकायों में स्वीकृत पदों में से 37 फीसदी खाली थे। वहीं, 16 राज्यों में स्थानीय निकायों के पास कर्मचारियों की भर्ती करने का अधिकार बहुत सीमित था या बिल्कुल नहीं था।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के लिए 2024 में तैयार एक शोधपत्र के अनुसार, एक दशक से भी अधिक समय से नगर निकायों की आय देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग एक फीसदी के आसपास बनी हुई है। सरकारी अनुदान से कोई शोधन संयंत्र बनाया तो जा सकता है लेकिन उसे लगातार चलाने के लिए नियमित आय की जरूरत होती है। वर्ष 2025 में तीन प्रमुख शहरों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि किसी भी राज्य में उपयोगकर्ताओं से लिया जाने वाला शुल्क, व्यवस्था की पूरी लागत को पूरा नहीं करता। इसके अलावा, अधिकांश निवासी इस तरह का शुल्क देने के इच्छुक भी नहीं थे। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण के दिशानिर्देशों में वर्ष 2021 में शहरों और राज्यों में प्रशिक्षित पेशेवरों का एक अलग काडर तैयार करने की जरूरत बताई गई थी। इसके बाद क्षमता निर्माण के लिए एक ढांचा तैयार किया गया, जिसके तहत कार्यक्रम इकाइयों, अनुबंध पर रखे गए शहरी प्रबंधकों और दो महीने की इंटर्नशिप के माध्यम से सहायता दी जाने लगी। प्रगति पहल के तहत चुने गए 50 शहरों में, बड़े महानगरों के साथ सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर तथा प्रमुख आर्थिक केंद्र भी शामिल हैं। इन्हें देश के दूसरे शहरों के लिए आदर्श के रूप में विकसित करने की योजना है। वर्ष 2025 के अध्ययन में कहा गया कि छोटे शहरों में सुधार तेजी से दिखाई दे सकता है, लेकिन पर्याप्त संसाधनों के अभाव में वह लंबे समय तक कायम नहीं रह पाता। पुराने कचरा स्थलों की सफाई का खर्च उठाना भी सीमित आय वाले छोटे कस्बों के लिए मुश्किल होगा। ऐसे में केवल बड़े शहरों को आदर्श घोषित करना पर्याप्त नहीं है।



सेवा संकल्प अभियान में मध्यप्रदेश के युवाओं का ऐतिहासिक कीर्तिमान

1.08 लाख से अधिक हस्तनिर्मित ग्रीटिंग कार्ड से दिया विकसित भारत एवं समृद्ध मध्यप्रदेश का संदेश

भोपाल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर संचालित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा, सामाजिक चेतना और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करने की अभिनव पहल की। अभियान में प्रदेश के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने एक लाख कार्ड निर्माण के प्रारंभिक लक्ष्य को पार करते हुए कुल 1 लाख 8 हजार 880 हस्तनिर्मित ग्रीटिंग कार्ड तैयार किए। 55 से अधिक जिलों के विद्यार्थियों ने सात संभागों के माध्यम से सहभागिता कर अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए विकसित भारत 2047 और समृद्ध मध्यप्रदेश का संदेश जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास किया।

अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों ने पर्यावरण एवं संसाधन संरक्षण, राष्ट्र निर्माण एवं शौर्य गाथा, सामाजिक चेतना एवं स्वास्थ्य, संस्कृति एवं विरासत, ज्ञान-तकनीक एवं नवाचार, कृषि एवं ग्रामीण विकास, काव्य एवं साहित्यिक अभिव्यक्ति तथा नारी शक्ति एवं समसामयिक विषयों पर ग्रीटिंग कार्ड तैयार किए। इन कार्डों में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता, कलात्मक कौशल और सामाजिक सरोकारों की प्रभावी अभिव्यक्ति देखने को मिली। पर्यावरण एवं संसाधन संरक्षण विषय के अंतर्गत जल एवं ऊर्जा संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त जीवनशैली तथा 'एक पेड़ माँ के नाम' जैसे विषयों को प्रमुखता दी गई। सामाजिक चेतना एवं स्वास्थ्य से जुड़े कार्डों में महिला सशक्तीकरण, मानसिक स्वास्थ्य, नशामुक्ति और 'अंगदानडूँमहादान' जैसे महत्वपूर्ण विषयों के माध्यम से जनजागरूकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश दिया गया। राष्ट्र निर्माण एवं शौर्य गाथा विषय पर विद्यार्थियों ने भारतीय सेना के शौर्य, विकसित भारत 2047 और समृद्ध मध्यप्रदेश की परिकल्पना को रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया। कार्डों के माध्यम से राष्ट्र के प्रति सम्मान, कर्तव्यबोध और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया गया। संस्कृति, पर्व एवं विरासत विषय के अंतर्गत दीपावली सहित विभिन्न पर्वों, मध्यप्रदेश की गोंड, मांडवा एवं भील चित्रकलाओं, लोकनृत्यों और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को स्थान दिया गया। विद्यार्थियों ने अपनी कलाकृतियों

के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हुए लोक परंपराओं के संरक्षण और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुँचाने का सार्थक प्रयास किया। ज्ञान, तकनीक एवं नवाचार विषय पर भारतीय ज्ञान परंपरा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के जिम्मेदार उपयोग और उद्यमिता जैसे विषयों पर कार्ड तैयार किए गए। कृषि एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत जैविक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। काव्य एवं साहित्यिक अभिव्यक्ति के माध्यम से विद्यार्थियों ने स्वरचित कविताओं और प्रसिद्ध साहित्यकारों की रचनाओं को कलात्मक रूप दिया। वहीं, नारी शक्ति एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत बालिका शिक्षा और समावेशी विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को अभिव्यक्ति मिली। कार्ड निर्माण एवं संकलन की प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर संचालित की गई। विद्यार्थियों द्वारा तैयार कार्डों को संबंधित महाविद्यालयों, जिला लीड महाविद्यालयों तथा अतिरिक्त संचालक कार्यालयों के माध्यम से संकलित कर उच्च शिक्षा विभाग के संचालनालय तक पहुँचाया गया। चयनित कार्डों की विशेष प्रदर्शनी आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा, नवाचारी सोच और सामाजिक संदेशों को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। सेवा संकल्प अभियान विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सामाजिक सरोकारों से जोड़कर संवेदनशील, जागरूक और उत्तरदायी नागरिक बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल है। हस्तनिर्मित ग्रीटिंग कार्ड के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी भावनाओं, विचारों और सामाजिक प्रतिबद्धताओं को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी। यह पहल शिक्षा को सेवा भावना, सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बनी है। चयनित कार्डों की प्रस्तावित प्रदर्शनी विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा उनके सकारात्मक संदेशों को व्यापक जनसमुदाय तक पहुँचाने का अवसर प्रदान करेगी।

आदर्श विद्यालयों से ही नई पीढ़ी संस्कारित होगी -मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मानव बाल कल्याण समिति के महाकालपुरम प्रकल्प का किया भूमिपूजन

मुख्यमंत्री ने प्रकल्प के लिए 1.25 करोड़ रुपये की घोषणा की

इंदौर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आदर्श विद्यालयों से ही नई पीढ़ी संस्कारित होगी। शिक्षा के नए प्रकल्पों की शुरुआत इस दिशा में एक शुभ संकेत है। विद्यालय व्यक्तिगत मान अपमान के लिए नहीं होते हैं। यहां पर सब लोग एक समान रूप में शिक्षा ग्रहण करते हैं। गुरु सांदिपनि की परंपरा का निर्वहन करते हुए उज्जैन से कृष्ण और सुदामा की नई पीढ़ी निकलेगी। डॉ. यादव रविवार को उज्जैन के जियापुरा में विद्या भारती की मानव बाल कल्याण समिति (विद्याभारती) के द्वारा निर्मित होने वाले बहुउद्देशीय महाकालपुरम प्रकल्प के भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में महाअष्टमी के दिन शिक्षा के एक नए चरण की शुरुआत हो रही है। पहले से ही उज्जैन में दो सरस्वती शिशु मंदिर संचालित हो रहे हैं जो कि मध्यप्रदेश बोर्ड के अधीन हैं। यह नया प्रकल्प सीबीएसई के अनुसार शिक्षण प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस प्रकल्प के लिए पूर्व में स्वीकृत किए गए 75 लाख के अलावा 1.25 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाकालपुरम का शिलान्यास एवं भूमि-पूजन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सांसद श्री अनिल फिरोजिया ने कहा कि विद्या भारती ऐसी संस्था है जहां पर बच्चों को सर्वांगीण विकास होता है। सांसद श्री फिरोजिया ने कहा कि मैं भी सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र रहा हूँ। यह ऐसी संस्था है जो छात्रों को अच्छा आचरण, संस्कार व नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। इस अवसर पर क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती श्री अखिलेश मिश्रा, संत श्री श्याम गिरी महाराज (राधे-राधे बाबा), महापौर श्री मुकेश टटवाल, गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री ओम जैन, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रवि सोलंकी, सिंहस्थ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री



जगदीश अग्रवाल, श्री राकेश पंड्या, मानव बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री गजेन्द्र मेहता, मानव बाल कल्याण समिति के सचिव श्री योगेश, पूर्व विधायक श्री राजेन्द्र भारती एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

सस्ती सौर ऊर्जा से बदलेगी भारत की तस्वीर, हरित इस्पात और एल्युमीनियम उद्योग को मिलेगा बड़ा मौका

भारत में ऊर्जा की लागत को लेकर हमारी सोच निरुत्साहित करने वाली रही है। देश में कोयले की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। उसे देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना महंगा पड़ता है। पेट्रोलियम और गैस के घरेलू दाम भी काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों से तय होते हैं। बिजली व्यवस्था में भी अक्सर व्यावसायिक उपभोक्ताओं से ज्यादा कीमत वसूली जाती है। इन सबका नतीजा यह होता है कि भारत में ऊर्जा की कीमत महंगी है।

भारतीय कंपनियों को मनमाने ढंग से तय होने वाली राज्य सरकारों की बिजली नीतियों, कमजोर बुनियादी ढांचे और बिजली-ईंधन सहित कच्चे माल की महंगी कीमतों के बीच अपना रास्ता तलाशना होता है। ऐसे माहौल में सफल होने का एक प्रमुख तरीका यह कि कंपनियां असाधारण बौद्धिक क्षमता वाले लोगों को अपने साथ जोड़ें और बाकी कमियों की भरपाई उनकी प्रतिभा से करें। इसी ताकत के दम पर भारतीय कंपनियों ने वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाई।

हालांकि अब ऊर्जा की कीमतों में आ रहा बड़ा बदलाव इस पुरानी सोच को बदल रहा है। पहली बार, भारत ऊर्जा की लागत के मामले में एक आकर्षक ठिकाने के रूप में उभर रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कली के निकित अभयंकर और अमोल फडके के हाल में आए एक शोध से इस बदलाव की कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। भारत में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए जितनी पूंजी की जरूरत होती है, वह अमेरिका की तुलना में अब लगभग एक-तिहाई रह गई है।

इसके पीछे तीन प्रमुख कारण हैं। पहला, इंटरकनेक्शन विलंब यानी बिजली संयंत्र को बिजली ग्रिड से जोड़ने में लगने वाला समय। दूसरा, मजदूरी की कम लागत और तीसरा, जमीन हासिल करने की लागत। हालांकि, पूंजी की लागत के मामले में भारत को नुकसान उठाना पड़ता है। इसकी एक वजह हमारी वित्तीय और आर्थिक नीतियों की खामियां हैं जिनमें पूंजी नियंत्रण भी शामिल हैं। इसके बावजूद, जमीन पर परियोजनाओं को कम लागत में पूरा करने का भारत का फायदा इस वित्तीय नुकसान से बड़ा साबित हो रहा है।

अब बिजली की लागत पर गौर कीजिए। दिन के समय मिलने वाली सौर बिजली की कीमत भारत में लगभग 30 डॉलर प्रति मेगावॉट घंटा है। अमेरिका में यही कीमत करीब 50 डॉलर प्रति मेगावॉट घंटा है। यदि सौर ऊर्जा के साथ बैटरी भंडारण की सुविधा भी जोड़ दी जाए ताकि जरूरत के मुताबिक चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा सके तो भारत में ऐसी बिजली की लागत लगभग 70 डॉलर प्रति मेगावॉट घंटा बैठती है। अमेरिका में इसके लिए करीब 100 डॉलर खर्च करने पड़ते हैं।

अमेरिका लंबे समय तक जीवाश्म ईंधन के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा की क्रांति को आगे बढ़ाने में भी अमेरिकी सरकार के शोध एवं निवेश की बड़ी भूमिका रही। परंपरागत सोच यह थी कि ऊर्जा की लागत के मामले में अमेरिका से मुकाबला करना, भारत जैसे देश के लिए लगभग असंभव है। अब यह तस्वीर बदल रही है और अब भारत बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। अमेरिका को ऊर्जा लागत के मामले में पीछे छोड़ना अपने आप में बड़ी बात है। अब अमेरिका के मुकाबले भारत में उत्पादन करने के दो स्पष्ट फायदे हैं, सस्ता श्रम और सस्ती ऊर्जा।

ऊर्जा की इस नई तस्वीर के कारण, भारतीय कंपनियों को अपनी कारोबारी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। आज भारतीय उद्योगों का बड़ा हिस्सा ऐसी परिस्थितियों में विकसित हुआ है जब ऊर्जा महंगी थी। वर्ष 1991 से 2007 के बीच व्यापार उदारीकरण के दौर में भारतीय कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। ऐसे में इन्होंने उन क्षेत्रों में अपनी जगह बनाई, जहां ऊर्जा की खपत कम होती थी।

इस रुझान की एक झलक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई)

के आंकड़ों में भी मिलती है। वर्ष 1992-93 में कंपनियों के कुल खर्च में बिजली, ईंधन और पानी की हिस्सेदारी 5.73 फीसदी थी। वर्ष 2024-25 तक यह घटकर केवल 2.87 फीसदी रह गई। लेकिन अब सस्ती स्वच्छ बिजली इस स्थिति को और बदल सकती है जिससे उद्योगों को चलाना ज्यादा लाभदायक हो सकता है।

इस बदलाव को समझने के लिए इस्पात उद्योग का उदाहरण बेहतर है। आज भारत की लगभग पूरी मौजूदा इस्पात उत्पादन क्षमता में कोयले की अहम भूमिका है। कोयला उत्पादन की प्रक्रिया में कच्चे माल और ऊर्जा दोनों के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन अब इसका एक तकनीकी विकल्प मौजूद है जिसे हरित इस्पात कहा जाता है। हरित इस्पात बनाने की प्रक्रिया में पहले बिजली की मदद से हाइड्रोजन तैयार की जाती है। फिर इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) प्रक्रिया में किया जाता है, जिसमें लोहे के अयस्क से स्पंज आयरन बनाया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएफ) में बिजली की मदद से इस लोहे को पिघलाकर इस्पात तैयार किया जाता है।

अब हरित हाइड्रोजन के कारण स्थिति बेहतर लग रही है जो कुछ साल पहले संभव नहीं था। सौर ऊर्जा और बैटरी से मिलने वाली बिजली के लिए कंपनियां 25 साल तक तय कीमत पर बिजली खरीदने का समझौता कर सकती हैं। दूसरी ओर, आने वाले वर्षों में कोयले की कीमतें बढ़ सकती हैं। इन दोनों बातों को जोड़कर देखा जाए तो भारत में हरित इस्पात की लागत अब पारंपरिक कोयला आधारित इस्पात के लगभग बराबर पहुंच गई है। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जैसे बाजारों में कार्बन उत्सर्जन को लेकर नियम सख्त हो रहे हैं। इस तकनीकी बदलाव से भारतीय इस्पात उद्योग के सामने एक अनूठा अवसर तैयार हुआ है। चीन का इस्पात उद्योग बड़े पैमाने पर कोयले और दूसरे जीवाश्म ईंधनों पर आधारित है। वहां हर साल करीब एक अरब टन इस्पात बनाने की क्षमता है। भारत के पास मौका है कि वह हरित इस्पात की उत्पादन क्षमता विकसित करे और लागत के मामले में चीन के इस्पात उद्योग को चुनौती दे। एल्युमीनियम उद्योग में भी कुछ ऐसा ही बदलाव संभव है। एल्युमीनियम बनाने के लिए बिजली की बहुत जरूरत होती है, लेकिन कोयला इसका कच्चा माल नहीं है। इस्पात की तरह ही एल्युमीनियम के मामले में भी अंदाजा मिलता है कि भारत में स्वच्छ बिजली से बनने वाला एल्युमीनियम, कोयले पर आधारित बिजली से बनने वाले एल्युमीनियम को लागत के मामले में टक्कर दे सकता है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा वाली बिजली की मौजूदा कीमतें और अगले 25 वर्षों तक उसके लिए रुपये में तय दर पर बिजली मिलने की सुविधा को ध्यान में रखें तो यूरोपीय संघ जैसे उन बाजारों में, जहां सीबीएएम लागू है वहां हरित एल्युमीनियम को निर्यात में अतिरिक्त बढ़त भी मिल सकती है। हम 2026 में एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं जहां ये गणनाएं लगभग बराबरी के स्तर पर हैं। अब आगे हरित तकनीकों का दबदबा बढ़ने के पीछे तीन पक्के कारण और भारत को लेकर दो उम्मीदें हैं। (क) अधिक देश सीबीएएम लागू करेंगे। (ख) सौर ऊर्जा और बैटरी तकनीक में प्रगति जारी रहेगी। इनके विकास के साथ हरित बिजली की लागत लगातार घटती रहेगी। (ग) महंगाई के साथ कोयले की कीमतें भी बढ़ेंगी। (घ) भारत में आर्थिक और वित्तीय नीतियों में सुधार की उम्मीद है। यदि इन सुधारों के तहत पूंजी के आवागमन पर लगे नियंत्रण हटाए जाते हैं तब पूंजी जुटाने की लागत घटेगी। इससे हरित बिजली की लागत भी कम हो सकती है। (ङ) भारत सरकार जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण को अधिक गंभीरता से ले सकती है। ऐसी स्थिति में कोयले पर कर बढ़ाए जा सकते हैं और उसके इस्तेमाल पर दूसरी पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। कंपनियों के बोर्डरूम और निवेश समितियों को अब कई पहलुओं पर अपनी रणनीति नए सिरे से तय करने की जरूरत है। भारत में उभरती इस बिजली आधारित अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले उद्योगों में निवेश के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। दूसरी ओर, बिजली, इस्पात और एल्युमीनियम जैसे क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन पर आधारित परिसंपत्तियों के भविष्य में बेकार पड़ जाने का जोखिम भी बढ़ गया है।

मध्यप्रदेश में निवेश हर दृष्टि से आपको लाभ देगा-मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आंध्र प्रदेश में की प्रमुख निवेशकों से भेंट

मध्यप्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए लागू की गई नीतियों की दी जानकारी जीआईएस 2027 के लिये किया आमंत्रित

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आंध्र प्रदेश में निवेशकों से मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापना का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा मध्यप्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास की प्रोत्साहनकारी नीतियों के कारण निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर उन्हें हर स्थिति में लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को आंध्र प्रदेश में निवेशकों से चर्चा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेश के नए अवसरों और औद्योगिक साझेदारियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में हो रहे कार्यों की जानकारी निवेशकों को दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा में बताया कि मध्यप्रदेश में उपलब्ध निवेश की व्यापक संभावनाओं और अनुकूल औद्योगिक वातावरण का लाभ सभी को मिल रहा है। राज्य सरकार की निवेश प्रोत्साहन की 25 सरलीकृत नीतियां विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आने में सहायक बन रही हैं। मध्यप्रदेश में धार जिले में पीएम मित्र पार्क और ग्वालियर में टेलीकॉम मैनुफैक्चरिंग इकाई में महत्वपूर्ण निवेश अब क्रियान्वयन की ओर है। हाल ही में जबलपुर-इंदौर औद्योगिक कॉरिडोर की योजना तैयार की गई है। यह कॉरिडोर प्रदेश के बड़े व्यापक भू-भाग की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की विजयवाड़ा में सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री विजय देवरकोंडा एवं अभिनेत्री श्रीमती रश्मिका मंदाना से भी भेंट हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश फिल्म शूटिंग के क्षेत्र में देश में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। प्रदेश की फिल्म-फ्रेंडली नीतियां, फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने में सफल हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों को जीआईएस-2027 का आमंत्रण देते हुए आयोजन की रूपरेखा की जानकारी दी जिसमें भोपाल में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक एकत्र होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि वर्ष 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी जिसमें 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए थे। इन प्रस्तावों में से एक तिहाई प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मोहन स्पिन्टेक्स इंडिया लिमिटेड के संस्थापक एवं प्रबंध संचालक श्री वी. सुधाकर चौधरी तथा श्री अनंत लक्ष्मी स्पिनिंग मिल्स के अध्यक्ष श्री सामिनेनी कोटेश्वर राव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दोनों उद्योगपतियों को धार स्थित पीएम मित्रा पार्क और प्रदेश के कपास उत्पादक क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। चर्चा में स्पिनिंग, होम टेक्सटाइल, बुनाई और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए प्रदेश में उपलब्ध अवसरों पर विचार-विमर्श हुआ। श्री चौधरी के साथ कृषकों के अध्यक्ष के रूप में जैव-उर्वरक, कृषि आदान और कृषि लॉजिस्टिक्स में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तेनाली डबल हॉर्स के प्रबंध संचालक श्री मोहन श्याम प्रसाद के साथ प्रदेश के दलहन उत्पादक क्षेत्रों के समीप दाल मिल स्थापित करने की संभावनाओं पर संवाद हुआ। कॉन्टिनेंटल कॉफी के महाप्रबंधक श्री मीनावल्ली बलराम से उत्तर और मध्य भारत के बाजारों में आपूर्ति के लिए मध्यप्रदेश में कॉफी ब्लेंडिंग, पैकिंग एवं वितरण केंद्र विकसित करने पर विचार-विमर्श किया गया। इंजीनियरिंग क्षेत्र में क्रिस्टना इंजीनियरिंग वर्क्स के संचालक श्री बी. राजा शेखर के साथ प्रदेश के सीमेंट, खनन और विद्युत उत्पादन क्षेत्रों की औद्योगिक आवश्यकताओं पर चर्चा हुई। इन उद्योगों के समीप कास्टिंग, मशीनिंग, कलपुर्जों और सर्विस सेंटर से संबंधित इकाइयों की स्थापना की संभावनाओं पर विचार किया गया। रामकोर ग्रुप के अध्यक्ष श्री के.वी.एस. प्रकाश राव से प्रदेश में वाणिज्यिक वाहनों और ट्रैक्टरों के डीलर नेटवर्क के विस्तार तथा ऑटो-सर्विस क्षेत्र में कौशल विकास पर चर्चा हुई। सिंहस्थ 2028 के दृष्टिगत पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में निवेश को लेकर फॉर्च्यून मुरली ग्रुप के प्रबंध संचालक श्री मुत्तवरपु मुरली (कृष्णा) से संवाद हुआ।



मुख्यमंत्री ने उज्जैन, इंदौर और ओंकारेश्वर में होटल व्यवसाय एवं पर्यटन सुविधाओं के विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधोसंरचना और नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। ऋत्विक् प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर एवं लोकसभा सांसद डॉ. सी.एम. रमेश तथा कंपनी के कार्यकारी संचालक श्री सी.एम. राजेश के साथ प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। कंपनी अधोसंरचना विकास, इंजीनियरिंग एवं निर्माण, सिंचाई, बांध निर्माण और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में कार्यरत है। बोंडाडा ग्रुप के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक डॉ. बोंडाडा राघवेंद्र राव के साथ भी प्रदेश में निवेश के अवसरों पर विचार-विमर्श हुआ। समूह नवकरणीय ऊर्जा, सोलर परियोजनाओं, टेलीकॉम और रेलवे अधोसंरचना के क्षेत्रों में कार्य करता है। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के प्रमोटर एवं संचालक श्री सी. गोविंद विश्वेश से अधोसंरचना और नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सीवीआर समूह से जुड़ी नवयुग इंजीनियरिंग एवं चिंता ग्रीन एनर्जी कंपनियां पुल, टनल, बंदरगाह, सिंचाई, सौर ऊर्जा, बैटरी भंडारण और पंपड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। खाड़ी देशों के निवेशकों से संपर्क बढ़ाने के लिए आईडीएफआईसी, दुबई के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस.एस. राजू से चर्चा की गई। इसमें खाड़ी देशों और प्रवासी भारतीयों के निवेश को प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने की संभावनाओं पर विचार हुआ। इंटरनेशनल स्टार्टअप फाउंडेशन, मिडिल ईस्ट के अध्यक्ष श्री रावुरी एस. राव के साथ मध्यप्रदेश के स्टार्टअप्स को खाड़ी देशों के निवेशकों और बाजारों से जोड़ने पर संवाद हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आंध्र प्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन के अध्यक्ष श्री पोतलूरी भास्कर राव से भी भेंट की। उन्होंने श्री राव को भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 में व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ सहभागिता के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण से भी भेंट हुई। इसके पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. यादव के विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गल्लवरम (आंध्र प्रदेश) पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों ने पुष्प-गुच्छों से स्वागत किया।

भोपाल में होगा फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026

भोपाल मध्यप्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात की संभावनाओं को नई दिशा देने के उद्देश्य से 23 अक्टूबर 2026 को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 का आयोजन किया जाएगा। मधुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री श्री नारायण सिंह पंवार ने बताया कि कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश सहित देश के अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन को आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयों, कोल्ड-चेन अधोसंरचना, मूल्य संवर्धन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाजारों से जोड़ना है। सम्मेलन में देश के प्रमुख निवेशक, निर्यातक, मत्स्य उद्यमी, स्टार्ट-अप्स और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाग लेकर मत्स्य उद्योग में निवेश एवं व्यापार विस्तार की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करेंगे। मध्यप्रदेश में लगभग 4 लाख 50 हजार हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जो अंतर्देशीय मत्स्य पालन, केज कल्चर और मत्स्य आधारित उद्योगों के विकास की व्यापक संभावनाएं प्रदान करता है। राज्य सरकार का प्रयास इस जल संपदा का बेहतर उपयोग कर मत्स्य उत्पादन के साथ प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात को प्रोत्साहित करना तथा मत्स्य पालकों की आय एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति-2026 तथा अंतर्देशीय राज्यों की मत्स्य निर्यात क्षमता को बढ़ाने से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया का विमोचन किया जाएगा। कार्यक्रम में एकीकृत केज कल्चर इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन भी होगा। साथ ही प्रदेश के जलाशयों एवं अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास से संबंधित परियोजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति-पत्र प्रदान किए जाएंगे। सम्मेलन में मत्स्य पालन से जुड़े हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य सहकारी समितियों, स्टार्ट-अप्स तथा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए जाएंगे। कॉन्क्लेव मध्यप्रदेश को अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन के साथ मत्स्य प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे मत्स्य क्षेत्र में नवीन निवेश आकर्षित करने, आधुनिक अधोसंरचना विकसित करने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने को गति मिलेगी।